The House reassembled after lunch at thirty-three minutes past two of the clock, **[The Vice-Chairman (Shri M. A. Baby) in the Chair.]**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): We shall take up the Short Duration Discussion· Shri Gurudas Das Gupta—absent. Shri Shankar Dayal Singh.

SHORT DURATION DISCUSSION

Likely Closure of certain public sector undertakings due to scarcity of funds and disinvestment of their shares by the Government

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात से आज खुशी हो रही है कि पिछले एक सप्ताह से लगभग यह महत्वपूर्ण विषय राज्य सभा की कार्यसूची में जोड़ा जा रहा था और एक सप्ताह से हम लोग इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब यह आए इस सदन के सामने और सच्चाई को प्रस्तुत किया जाए । आज जाकर यह मौका मिला है । जिस विषय पर चर्चा की अनुमति प्रदान की गई है सरकार उससे अच्छी तरह से उसकी गम्भीरता से परिचित होते हुए भी अपरिचित है । निधियों के अभाव के कारण सरकारी उपक्रमों में से अधिकांश के बंद होने की आशंका और संभावना है और दूसरी ओर ...

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Sir, the Minister concerned is not present· (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): I think Mr. Jacob will see to it. The hon. Member raised this issue that the concerned Minister is not present in the House. You may kindly try to see to that without much delay· (*Interruptions*)

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: No, first I want that the Minister should come here. I thought, perhaps, the Minister is here. (*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): The Minister was here right from the morning. (*Interruptions*) The Minister of State for Home Affairs is also here.

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: No, no, no. It is a very serious matter. The Minister should come here. Without the Minister concerned here I am not going to proceed with it· What is this? This is a mockery. ...(*Interruptions*)... It seems the Government is not serious at all. ...(*Interruptions*)... No, no. this is not the way. The Ministe concerned is not here...(*Interruptions*)...

SHRI V· NARAYANASAMY: Two Ministers are here. Two ministers are sitting...(*Interruptions*)...

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: The Government is not at all serious Therefore, Sir, I want you to give a ruling that the Minister concerned should come here just now. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): He should come. He should come·

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Perhaps, he might have mistaken that the clarifications would continue.

(*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Shankar Dayalji, let Mr. Jacob speak. ...(*Interruptions*)... Please, sit down. Just a minute. Let the Minister clarify.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI (M. M. JACOB): The Minister is on his way. He is coming. The Minister is on his way. Meanwhile, in order to continue our functioning another Minister here is taking note of what you have said. The Minister concerned is just coming. He is on the way.

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: he comes. I want that it should go on record. Sir, I request you to adjourn the House because the Minister concerned is not here. The Government is not

at all serious regarding this matter. Therefore, I request you to kindly adjourn the House for ten minutes.

AN HON. MEMBER: No, no, no. Other Ministers are present.

SHRI M. M. JACOB: No, no, no. This is not the way... (*Interruptions*)...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I know pretty well that the Minister of State for Industry, Mr. Thungon, was here right from the morning. He was here in this House. The other Minister is here to take note of what... (*interruptions*)...

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: The House is not concerned whether he was present here from the morning or through the night. The Home is concerned with his presence here at this time. ...(*Interruptions*)... No, it is a very grave and serious matter. Sir, please adjourned the House or let the Minister come.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: He is on the way.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): I understand the worry that is being expressed by some of the hon. Members. It would have been ideal if the Minister concerned is present here and, in fact, during the morning-time the Minister was present here, but that is not the justification for the Government to create such a situation. I think the Government will take due note of it and at the same time you will appreciate that there is collective functioning of the Ministry. Though Ministers are here, but I am not happy with the fact that the concerned Minister is not present at this moment. I think in future the Government will take due note of it and see that such a situation should be avoided. Let us proceed with the functioning of the House... (*Interruptions*)... Please cooperate with me.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: What more do you want than this strong remark?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): The Minister is here

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY AND DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES) (SHRI P. K. THUNGON): Sorry,

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आपने जो व्यवस्था दी है वह सराहनीय है । लेकिन मैं समझता हूं कि राज्य सभा जो उच्च सदन है, इसकी हमेशा उपेक्षा होती है । यहां मंत्री लोग और संबंधित मंत्री रहते ही नहीं हैं । आपने जो रूलिंग दी है, मैं समझता हूं कि पूरे आधार के साथ और प्रमाण से तो नहीं कह सकता, लेकिन इस तरह की व्यवस्थायें बार बार दी गई हैं कि मंत्रीगण और संबंधित मंत्री सदन में मौजूद रहें । लेकिन इसकी बार बार उपेक्षा होती है जो चिन्ताजनक है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): The Minister is there.

श्री शंकर दयाल सिंह : उपसभाध्यक्ष जी, मुझे खुशी है कि आपने बहुत अच्छी व्यवस्था दी है और इससे भी ज्यादा खुशी है कि मंत्री महोदय आए । लेकिन वे भी विपक्ष के रास्ते से आए, उस रास्ते से नहीं आए । इसलिए कि वे जानते हैं कि सही रास्ता यही है । इसके लिए मैं श्री थूंगन को धन्यवाद देता हूं कि वे सही रास्ते से आए है और सही जवाब भी देंगे ... (**व्यवधान**)

श्री पी० के० थूंगन : बीच के रास्ते से आए हैं ।

श्री शंकर दयाल सिंह : उपसभाध्यक्ष जी, जिस गम्भीर विषय पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं उसको लेकर सारा देश चिन्तित है । जब सरकार की उद्योग नीति सामने आई, नई उद्योग नीति के बाद नई आर्थिक नीति समने आई । उसके बाद से देश में खासकर सार्वजनिक उपक्रमों के क्षेत्र में एक हलचल, एक आशंका सी मच गई है ।

उपसभाध्यक्ष जी, ये सरकारी उद्यम ये उपक्रम माल व्यावसायिक संस्थान नहीं हैं लेकिन इन्हें कोई बनिए की दुकान भी नहीं कह सकता, जिसका उद्देश्य केवल एक हो कि यहां हम दुकान खोलकर बैठ जांय और हम केवल लाभ कमायें । भारत में आजादी के बाद जब सार्वजनिक उद्योगों

[श्री शंकर दयाल सिंह]

की कल्पना की गयी तो उस समय बहुतों को याद होगा कि अनेक ऐसे दुनिया के देश थे, जिन्होंने कहा कि आप अपने यहां बड़े बड़े ज्वाइंट सेक्टर मत बिठाओ । लेकिन यह जवाहर लाल जी की दूरदर्शिता थी, आजादी के बाद हमारे बड़े बड़े नेताओं के मन में जो भविष्य की ,कल्पना की कामना थी, उसके कारण उन्होंने कहा कि नहीं, हम दूसरे देशों के मोहताज नहीं बनेंगे और हमारे यहां जो संस्थान हैं उनको लेते हुए हम अपने देश में औद्योगिक प्रतिस्थान खड़े करेंगे । इसीलिए इस देश में जब पहले पहल दिन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना की गयी और उनका जब उद्घाटन भाषण हुआ तो उनको पंडित जवाहर लाल नेहरू ने राष्ट्र को समर्पित करते हुए कहा था कि आजाद भारत के यह बड़े तीर्थ-स्थल हैं । आज उन्हीं तीर्थ-स्थलों के संबंध में हम सदन में गंभीर चर्चा करने जा रहे हैं । उपसभाध्यक्ष महोदय, आखिर उनका उद्देश्य क्या था ? सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना को सबसे बड़ा उद्देश्य यह माना गया कि एक ओर जो पिछड़े क्षेत्र हैं, वहां पर उनको कायम करके उनके पिछड़ेपन को दूर किया जाय, देश में सार्वजनिक कल्याण किया जाय, बेरोजगारी दूर की जाय और बाद में जो बहुत से रुग्ण संस्थान हैं, उनके बारे में भी सोचा जाय ताकि कहीं मजदूर बेकार न हो जांय और वे बिल्कुल समाप्ति की ओर न चले जांय । इसलिए सरकार ने 72 और 73 में जाकर रुग्ण मिलों को अपने हाथ में लेने की नीति बनायी । आज जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने इन उपक्रमों को लेकर है, उसके संबंध में यह मानता हूं कि आज ये सारे उपक्रम जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित हुए थे, इसमें ये सफल नहीं हुए हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं । ये सफल इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि सरकार की स्वयं की नीति इनके प्रति उचित नहीं है, इनको सफल बनाने की नहीं है । इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि आज देश में चाहे 236 पब्लिक सैक्टर हों या 250 हों, उनके जो आंकड़े हमारे सामने हैं, और जो आंकड़े बराबर सरकार की ओर से जाते हैं तो अगर लेटेस्ट आंकड़ों को हम देखें तो उनसे यह साफ जाहिर होता है कि उनकी सबसे बड़ी समस्या पूंजी की समस्या है । लाभ कमाकर जिन उपक्रमों ने सरकार के कोष में पैसा दिया, उनके विकास के लिए भी सरकार पैसा नहीं दे रही है और बड़े बड़े उपक्रम भी आज खराब स्थिति में हैं । मार्डनाइजेशन के लिए या उनके विकास के लिए या उनकी आपूर्ति के लिए भी सरकार उन्हें फंड मुहैया नहीं करा रही है । साथ ही सरकार उनका पैसा कहीं डाइवर्ट कर रही है ? बड़े बड़े शेयर कैपिटल्स में, जिसको लेकर इस सदन में भारी हंगामा होता रहा है । उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूं, मैं यहां पर एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं । एच०ई० सी०, हैवी इंजिनियरिंग कारपोरेशन का मामला इस सदन में उठा था । मुझे आज भी उसकी तिथि याद है । 30 मार्च, 92 को इन्हीं मंत्री महोदय श्री थुंगन जी ने यहां पर जवाब देते हुए कहा था कि उसकी हालत इसलिए खराब हो रही है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है । इस कारण जो उसको आदेश मिले हैं उनकी आपूर्ति भी एच०ई०सी० नहीं कर सकता है । इसी सदन में उन्होंने यह कहा था कि 110 करोड़ रुपए की उनकी मांग थी और उन्होंने कहा था कि 66 करोड़ रुपया उसको तुरंत दिए जायेंगे । यह जवाब भी उनकी ओर से आया था जब कि उसके पास 700 करोड़ रुपए के आर्डर थे ।

सरकार अगर चाहेगी तो पांच सौ करोड़ का आर्डर मिल सकता है । सरकार ने जो वायदा किया, उसकी पूर्ति नहीं की । एक सेक्टर का उदाहरण मैंने आपके सामने रखा । इसी तरह के और उदाहरण सभी सेक्टर्ज के हैं । उस लिहाज से फिगर्ज भी हमारे पास हैं जो सरकार ने मुहैया कराई हैं आज मैं 236 की बात नहीं कर रहा हूं । लेकिन 52 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स/ अंडरटेकिंग्ज के जो हमारे पास लेटेस्ट कागजात प्रस्तुत किये गये हैं उनमें 25 ऐसे यूनिट्स हैं जो नुक्सान में चल रहे हैं और 27 ऐसे यूनिट्स हैं जो लाभ में चल रहे हैं । आप लाभ-हानि की बात

को थोड़ी देर के लिए एक ओर रख कर सोचें कि आखिर इनकी उपयोगिता क्या है ? राष्ट्र केवल नक्शे पर नहीं बनता है, राष्ट्र केवल इतिहास और भूगोल नहीं है, राष्ट्र एक सतत विकासशील प्रक्रिया है और उस राष्ट्र के लिए कुछ खास चीजें होती हैं जिनको लेकर वह राष्ट्र दुनियां में अपने आप को स्थापित कर सकता है । इसी तरह से आज औद्योगिक और आर्थिक नीति को सब से अधिक महत्व दिया जाता है । सोवियत संघ पिछले दिनों फेल हुआ और वहां पर बहुत बड़ी तबदीली आ गई । पिछले सालों में ऐसा क्या हुआ जिससे वहां बदलाव आया ? वह इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने आर्थिक रूप से संतुलन बरकरार नहीं रखा । उनके यहां औद्योगिकरण 72 प्रतिशत हो गया था और कृषि को इतना नेग्लेक्ट किया गया कि वह 25 प्रतिशत तक चली गई । हमारे यहां आजादी के बाद जब शुरुआत हुई तो हमारी एग्रीकल्चरल इकोनोमी 80 प्रतिशत पर थी लेकिन आज 32 प्रतिशत पर है । उद्योग हमारे यहां 16 प्रतिशत पर थे, आज हमारा उद्योग काफी आगे बढ़ा है । लेकिन जिस उद्योग के बढ़ने को ले कर हम दुनियां के नक्शे में आगे बढ़े थे, उनके प्रति सरकार की जो नीति है, उसमें बदलाव आ रहा है । नयी आर्थिक नीति और औद्योगिक नीति के बाद सब से बड़ा बदलाव वह आया कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के हमारे बड़े-बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं उनको किसी प्रकार से आपने बद करवाया, बदनाम करवाया, उनको परफॉरमेंस लेअर करा दो जिससे इनको हम मिट्टी के मोल दूसरों के हाथों में बेच दें या सौंप दें या इनको बेचद कर दें । इ1 इनको हम मिट्टी के मोल दूसरों के हाथों में बेच दें या सौंप देना इनको बंद कर दें । इस आशंका से यह देश आज काफी ग्रसित हो रहा है । यह सब से बड़ा अन्याय होगा और अन्याय इसलिए होगा कि दूसरी कम्पनियां कमाने के लिए टूथ पेस्ट बना सकती हैं, साबुन बना सकती हैं, बढ़िया कपड़े का उत्पादन कर सकती हैं लेकिन सामरिक अस्त्र वह नहीं बना सकती हैं, खाद के कारखाने नहीं बैठा सकती हैं, इंजीनियरिंग की जो चीजें हैं उनकी रुचि उसमें नहीं हैं । उनकी रुचि पैसे की ओर तथा लाभ की ओर है, उनकी रुचि राष्ट्र निर्माण की ओर नहीं है । पब्लिक सेक्टर में जो बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, वे लाभ के लिए नहीं हैं बल्कि प्रतिष्ठा के लिए हैं, देश को ऊंचा उठाने के लिए बनाए गए हैं । आपको अच्छी तरह से से याद होगा कि जब पहली बार हिन्दुस्तान में यह हुआ कि यहां स्टील प्लांट्स बैठाए जाएं तो अमरीका और इंग्लैंड ने आफर किया था कि आपको स्टील प्लांट बैठाने की जरूरत नहीं है, हम आपको यहां से बना कर दे देंगे । जब पहली बार हिन्दुस्तान में यह हुआ था कि तेल की खोज आरम्भ की जाए तो बड़े बड़े राष्ट्रों ने यह कहा था कि आप अपने यहां ड्रिलिंग मशीनें लगा कर इतना क्यों खर्च करेंगे ? जवाहरलाल जी को अमरीका आदि देशों ने पत्र लिख कर यह कहा था कि आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है । आपको अगर तेल की जरूरत है तो हम आपको तेल की आपूर्ति कर देंगे । लेकिन उन दूरदर्शी नेताओं ने भविष्य को देखा और यह विचार किया कि अगर किसी तरह का सामरिक संकट आ जाए तो क्या होगा या कोई दूसरा संकट आ जाए तो क्या होगा ? उन्होंने यह कहा कि हम दूसरों के मोहताज नहीं बनेंगे, दूसरों के हाथों अपनी आजादी को नहीं बेचेंगे । इसलिए उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र का बड़ा नक्शा हमारे यहां तैयार किया था । जो नक्शा तैयार हुआ, मैं 236 की बात नहीं कह कर केवल 20 को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं । आज जो हमारे यहां बड़े उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, उनमें 10 ऐसे हैं जो अभी नुक्सान में चल रहे हैं । जैसे राष्ट्रीय इस्पात निगम, हिंदुस्तान उर्वरक निगम, दिल्ली परिवहन निगम, भारतीय उर्वरक निगम, निर्यात ऋण एवं गारंटी निगम, इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, भारतीय इंजीनियरिंग निगम, भारत कोकिंग कोल, वेस्टर्न कोल फील्ड्स, इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड 3,063.68 करोड़ का इनका घाटा 1990–91 तक दिखाया गया है । दूसरी ओर 10 ऐसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र हमारे पास हैं जो लाभ में चल रहे हैं जैसे तेल व प्राकृतिक गैस आयोग, भारतीय तेल निगम, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, महानगर टेलीफोन्स, इस्पात अधिकरण, भारत

[श्री शंकर दयाल सिंह]

पैट्रोलियम निगम, हिंदुस्तान पैट्रोलियम, भारतीय रेलवे वित्त निगम, जहाजरानी निगम और निवेली लिग्नाइट। ये 6,882.91 करोड़ रुपये के लाभ में 1990-91 तक हैं। लेकिन इससे अलग हटकर मैं तो दूसरा सवाल करने वाला हूं। दूसरा सवाल, उपसभाध्यक्ष जी इसलिए करना चाहता हूं कि सरकार को अपनी मंशा साफ ढंग से रखनी चाहिए, जैसे तीन तीन कमेटियां भी सार्वजनिक उपक्रमों के संबंध में है और तीनों उप समितियों ने यह कहा कि इनका विकास हम किस तरह से कर सकते हैं। संसद के दोनों सदनों में मांग की गयी थी कि उनके आधार पर एक श्वेत पत्र सदन के सामने रखा जाए कि सच्चाई क्या है। सरकार अब तक इसमें फेल रही है। हमारे सामने कोई श्वेत पत्र नहीं रखा गया। जब से घाटे के सार्वजनिक उपक्रमों को बंद करने, बेचने की बात चली है तब से वहां का उत्पादन बुरी तरह गिर गया है। उत्पादन इसलिए गिर रहा है कि जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनके अंदर यह भावना घर कर गयी है कि पता नहीं किस दिन हमारे हाथ से किसी बड़े औद्योगिक घराने को यह सौंप दिया जाएगा। मजदूरों के अंदर एक दहशत फैल गयी है कि हमारे भविष्य का पता नहीं क्या होगा। कब ये बंद हो जाएंगे, कब हमारी छंटनी हो जाए। तीसरी ओर, जो फिजूल खर्ची की मार उनके ऊपर पड़ती है उसकी ओर सरकार ने सदन में कई बार जरूर कहा है लेकिन ध्यान नहीं दिया है। ध्यान किस लिए नहीं दिया है। और बड़ी बातों की ओर न जाकर एक उपक्रम का उदाहरण मैं माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। बहुत दूर जाने की बात नहीं है। सिन्द्री खाद कारखाने को लीजिए जो देश में सबसे पहला पब्लिक सेक्टर है। पहला पब्लिक सेक्टर में, सिन्द्री खाद कारखाना बना। जवाहर लाल जी ने उदघाटन किया और जब कोई हमारा बाहरी मेहमान आता था तो डी०वी०सी० और सिन्द्री कारखाना दिखलाने जाते थे कि हम सार्वजनिक क्षेत्र में किस तरह से प्रगति कर रहे हैं। अब वह जो आपका कारखाना है वह बंद पड़ा हुआ है, बिल्कुल समाप्त होने की स्थिति में है जबकि उर्वरकों की आपके यहां बहुत बड़ी कमी है। उसकी स्थिति क्या है? एक सिन्द्री कारखाने को ले लीजिए तो उस सिन्द्री कारखाने के लिए अभी तक आपके यहां 178 करोड़ रुपया का घोटाला अधिकारियों के टी०ए०, डी० ए० और बड़े बड़े होटलों में ठहरने के बिलों के कारण हुआ है। अतः इन स्थितियों के कारण यह सार्वजनिक क्षेत्र इस कगार पर पहुंच रहा है। दूसरी ओर आपने अपना 15 अरब रुपया पिछले दिनों शेयर मारकेट में फ्लोट कर दिया है। शेयर्स खरीदे। एक ओर तो आप सार्वजनिक उद्योगों को पैसे पैसे के लिए तरसा कर मार रहे हैं, सदन में आपने आश्वासन दिया कि हम नको इस तरह से पैसा देने जा रहे हैं लेकिन दूसरी ओर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं किस चीज पर? शेयर मारकेट पर। जिन कम्पनियों का पैसा आपने शेयर मारकेट पर लगाया अगर उन्हीं का कुछ पैसा लेकर, जिन पब्लिक सेक्टर कम्पनियों की स्थिति खराब है, उनमें लगाया होता तो वे आपके लिए लाभ की चीज होती। अगर हम गाय को घास न दें, भूसा न दें, खिलायें नहीं तो दूध कहां से देगी। दुधारू गाय को खिलाना चाहिए। लेकिन हम उसको चारे के लिए तरसा कर भी यह चाहते हैं कि उससे कुछ हासिल करें। यह कैसे होगा। यह कैसे होगा। अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट है सरकार ने 6 जुलाई को जो चीज प्रस्तुत की है उसके अनुसार 15 अरब रुपये के शेयर पहले तो था कि कोई ले ले। बाद में 33 कंपनियों का हुआ, बाद में 19 कंपनियों पर किया गया। हमारे पास 14 ऐसी कंपनियों के हैं जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट फर्स्ट राउंड में करीब 15 अरब रुपये का किया है और सैकण्ड में करीब 16 अरब रुपये का किया है, जबकि पूरे पब्लिक सैक्टर में आपके टाप मोस्ट में अगर हानि में आपके उपक्रम चल रहे हैं और उनकी हालत अगर खस्ता है, जिसका उदाहरण हमने आपको एच. ई०सी० से दिया, उसको आपको कितना देना है, 66 करोड़ रुपया देना है। वह भी आज नहीं दे पा रहे हैं। जबकि उप-

सभाध्यक्ष जी, इसी सदन में माननीय

मंत्री महोदय जो कि यहां बैठे हुए हैं और हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, उन्होंने भी हमको जवाब में कहा कि हम रांची को भारी इंजीनियरिंग कारखानें को देने जा रहे है, जवाब इन्होंने दिया है कि हम इसको देने जा रहे है, यह जवाब भी हमारे पास है जो कि उसमें मैं समय नहीं लेना चाहता हूं, अब जो सब से जरूरी चीज है जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि पिछले साल 14 जुलाई, 1991 को इसी सदन में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। उसमें 3 सूत्र कहे गए थे मुख्य रूप से जब इसी सदन में अनेक माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया था कि औद्योगिक क्षेत्रों का क्या होगा तो सरकार ने उनकी गारंटी लेते हुए निश्चित रूप से यह कहा था कि हम उनका अहित नहीं होने देंगे। हालांकि उपसभाध्यक्ष जो, दुख की बात यह है कि सरकार एक है भारत सरकार, लेकिन उस संबंध में उसके चार मंत्रियों के चार बयान आए। थुंगन साहब का इस संबंध में बयान आया कि हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं कि जो लाभ का नहीं हो रहा है उसका हम क्या करें। चिदम्बरम साहब का इसके ऊपर बयान आ गया कि हम इसको बंद भी कर सकते हैं, प्रधान मंत्री जी का इसके ऊपर बयान आ गया कि नहीं, हम किसी रूप से इसको बंद नहीं होने देंगे। यह उन्होंने कहा। तो तीन-तीन, चार-चार तरह की बातें यहां पर आईं। मैं सरकार से अभी दो-तीन-चार बातें जानना चाहता हूं, उनकी ओर उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं इसलिए कि मैं ज्यादा समय नहीं लेकर हम चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे मित्र इसके बारे में बोलने वाले हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री एम० ए० बेबी) : आपका समय एक्सीड हुआ।

श्री शंकर दयाल सिंह : मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। देखिए 3–4 बातें जानना चाहता हूं। पहली बात यह है कि एक श्वेत-पत्र जारी करते हुए सरकार इस सदन को विश्वास में ले और विश्वास में लेते हुए केवल तीन बातें करे। पहली बात यह है कि जो सरकारी कारखानें हैं जिनमें आप कुछ उत्पादन कर सकते हैं सरकारी फर्मों के आर्डर उनको मिलने चाहिए बनिस्बत कि आप बाहर दें। जैसे दुर्गापुर, भिलाई, बोकारो इस्पात कंपनियों के माडर्नाइजेशन का आपने प्लान बनाया और उस पूरे-पूरे प्लान में हम समझते हैं कि लगभग आपने मेरी समझ में जो भी पैसा यह किया है उसका हार्डली 10 प्रतिशत एच०ई०सी० से आपने खरीदा और बाकी या तो प्राइवेट लोगों को आपने दिया या फारेन में उसका आदेश दिया। हम यह चाहते हैं कि आप एक निश्चित योजना बना लें कि हम आदेश जो है वह पब्लिक सक्टर को दें। जिनकी हालत खराब है उनको आप पूंजी दे दीजिए। तीसरी बात की आप गारंटी दीजिए कि हम उनको बेचेंगे नहीं और हम उनको बंद नहीं करेंगे। आप देखिए कि आपका उत्पादन चलने लगेगा।

3.00 P.M.

मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त करूं उसके पहले एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि हमारे बिहार के अंतर्गत जो भारत सरकार के पब्लिक सैक्टर हैं उनके साथ बड़ा सौतेला व्यवहार हो रहा है। अभी वहां कोयला, लोहा, हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, बरौनी थर्मल पावर सिंदरी का कारखाना, बरौनी उर्वरक कारखाना, अबरक खान, मिटको, पाइराइट्स कारखाना और भी कुछ है। इतने पब्लिक सेक्टर में चल रहे हैं। अब देखिए, एच०ई०सी० ने अगर आपको 99 करोड़ का घाटा दिया तो दूसरी ओर दूसरे जितने भी लोहे के कारखाने हैं, वे जहां घाटे में चल रहे हैं वहीं बोकारो जो है बिहार में ही पब्लिक सेक्टर का, उसने तीन सौ करोड़ का लाभ दिया है एक सेक्टर में। अगर सिंदरी ने आपको नुकसान दिया है तो कोल इंडस्ट्री ने, आप जानते हैं कि वह कोयले का सबसे बड़ा कारखाना है बिहार में वह इस साल पांच सौ करोड़ के घाटे को समाप्त करके उसे लाभ की ओर ले गए हैं। तो हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं बड़े ही आदर के साथ कि बिहार में जो भारत सरकार के उपक्रम हैं जिनकी कि हालत खराब है और वह

[श्री शंकर दयाल सिंह]

खराब इसलिए है कि आप उनको पैसा नहीं दे रहे हैं, आपने आठवीं पंचवर्षीय योजना में आपने हालत खराब कर दी है और आप इस बात पर तुले हुए हैं कि इनको इतना खराब कर दिया जाए कि वे बंद होने की कगार पर पहुंच जाए, मैं चाहूगा कि आप उनकी अविलंब मदद करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह आज इस बात का एलान करे कि हमारे जो भी पब्लिक सेक्टर ऐसी स्थिति में हैं, उनके लिए आप संसद सदस्यों की एक जांच समिति बनाएंगे। हम ऐसा आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसे आपको गंभीरता से लेना चाहिए जोकि सरकार नही ले रही है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज सदन में ही मिल गया जबकि डिस्कशन की शुरूआत हो गयी और मंत्री महोदय का पता नहीं था। हाउस एडजॉर्न होने की बात चलने लगी। अब जब मंत्री महोदय आ गए हैं तो मैं चाहूंगा कि आज अनुपस्थिति के प्रायश्चित में सरकार निश्चित रूप से इसकी घोषणा करेगी जिससे कि यह सदन, यह देश और देश के साथ सारा पब्लिक सेक्टर इस विषय में आश्वस्त हो सके। धन्यवाद।

SHRI JAGESH DESAI: Mr Vice-Chairman, Sir. several speakers have discussed the working of the public sector. But at present, we are going to discuss particularly the disinvestment policy and the closure of the public sector undertakings. Before that, I would like-to state one thing and that is we hate created an impression in the mind of the people that public sector undertakings are eating away the finances of the country. Every time the Minister makes a statement., I caution the Government that this type of satement will not help. We are all commited that we want to see that the public sector rises to commanding heights. May be, we might not have achieved it But that is our goal. Sir, if I have seen the working of the public sector undertakings—even the Government has also admitted—85 per cent of the capital invested in the public sector is giving a fairly reasonable dividend. In spite of that, day and night what we are hearing is that the public sector is a burden on the exchequer. I would like to place before this august House that in the earlier years it was in losses. But, for the last 6 or 7 years, after the late Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi made a categorical statement that "I want a very, very dynamic, healthy public sector" and he himself was monitoring the perfomance of the public sector, I am happy to say that it has paid dividents. He was the first Prime Minister who had given financial assistance to public sector by allowing them to borrow on bonds and interest on them was free of income tax. And that helped the public sector to mobilise the resources. Today, the problem is that the Government always plead before this House that we have no resources and that is why we are not able to support the public sector. But it is your baby and it is the country's baby and, therefore, all of us have to take care of this baby. If it is sick, we have to find out what the reasons are. We have taken over several sick units, 59 or so, and, out of these units, 42 are under losses. Is it the fault of the policy on the public sector? We wanted to give employment and that is why we have taken over the losses of such public sector undertakings as were taken over by the private sector, in the year 1989-90, amounted to Rs. 480 crores and the total losses of those companies which were taken over from the private sector amounted to Rs. 3,000 crores. Is it the fault of our public sector policy? I feel that the Government should try to find out the causes for this. In this connection, I would like to offer some suggestions for the financial performance of the public sector before I go into the other aspects.

I would like to stress the point here—it has been admitted by the Government in this document here in December 1991—that 85 per cent of the capital invested is giving an eight-per-cent return after tax. This is after tax. Normally, the public sector units are established for purposes of creating infrastructure which in turn would help the privae

sector for building the industrial base in the country and we are doing that. In spite of that, we are hearing often that even the infrastructure companies should give a fair return. Then, what is the definition of return? The Government should tell us now. They must tell us whether a return of eight per cent on the investment made is enough or not. If it is not enough, then the Government must have one committee, look into all the infrastructure companies, the benefits the Government gets and the country gets and the private sector gets from them, and then they should decide what percentage of return they expect on the investment made in the infrastructure companies. But the Government has not done any study at all and yet everytime they tell us that they are not doing well. I am afraid that if we are not going to give enough resources to the public sector, if we are not going to see that the old machineries are replaced and if we are not going to see that modernization takes place, the whole public sector will go to dogs. Are we aiming at that? If not, then I would like the Government to ponder over the question as to how they can financially help these companies. Only today I read in the papers that the UTI, in one scheme, in one scheme alone, collected Rs. 4,500 crores, just in fixe or six dyas! These are all contributions by the people and these contributions are from the people, not from industrialists. The deposits are not from industrialists, but from others from those who save that is the middle-class and lower-middle class people. So, can they not give money to the public sector? I am unable to understand why the Government is not forcing the banks and others to give them advances. If the banks cannot give it, the Government mus give it. I say this because we must see to what extent the exchequer gets contribution from the public sector. In the Sixth Plan, they got Rs. 27,570 crores from Excise, Customs and from Corporation Tax, and also from dividends.

[The Vice-Chairman (Shrimati Jayanatarajan) in the Chair]

And, Madam, in the Seventh Plan, they got Rs. 57,873 crores from the public sector. When the public sector gives so much to the exchequer, is it not the duty of the Government to pass on some of its revenues to the public sector also? And, what is the budgetary support that they have got in the year 1990-91? They got Rs. 20,000 crores from the public sector by way of Excise, Customs, dividents, and Corporation Tax. And what is the budgetary allocation? I am very sorry to say that it is only Rs. 4575 crores. For the earlier year, it was Rs. 5450 crores but in the year 1990-91, you brought it down by one thousand crores of rupees. Is the way in which we are going to help the public sector when you are getting to much revenue from it? Don't only look at the profit, because the private sector will conceal everything in the matter of excise duty and costoms with the collusion of some officers; they can even play this game in the matter of income tax and corporation tax. But the public sector cannot do that. They are giving you a revenue of Rs. 20,000 crores in one year, and your budgetary allocation is only Rs. 4575 crores. Can we increase that allocation or not is the main question.

Now I come to disinvestment. I must make it very clear because you wanted to see that the deficit is reduced to 6 or 6.5 per cent of G.D.P. I think Mr. Yashwant Sinha was the Chanakya of the scheme of disinvestment but it was not implemented at that time and now you are starting it. But what are you getting? You are getting only Rs. 2500 crores. It is because all this exercise was done in great haste only to see that your Budget deficit is reduced to 6.5 per cent. Madam, they did not care to evaluate the assets as they stood on that day. I personally feel that a Committee of Parliament should be appointed along with some experts to ascertain the real value of the assets and shares on that particular day. I will give you a small example. Most of the public sector undertakings are located in big cities like Madras, Bombay, Calcutta, Hyderabad, Bangalore etc. What is the land cost in these cities? I must have visited the premises of not less than 60 public sector undertakings as member

[Shri Jagesh Desai]

of the PUC. In one case I found that there was a vast chunk of land with them for future expansion. You take the example of Rashtriya Chemicals and Fertilisers in Chembur, Bombay. There, the land cost per sq. metre is not less than Rs. 10,000. Have you taken into account the cost of land available with them? I have also heard and I do not know how far it is true, that there was disinvestment in shares of IPCL by taking the value of the share at Rs. 40 per share whereas I am told that unofficially it is quoted at Rs. 600 per share, that is 15 times the book value. Same position may be obtaining in respect of other companies' shares also. Now the assets they own had been acquired by them long before and while evaluating those assets, you have to take their present value minus the depreciation cost in respect of the total fixed assets of these public sector undertakings, such as their land godowns, guest houses, plants and machinery. Whereas the book value of those assets would be only Rs. 69 thousand crores, the present value may be around Rs. 6 lakh crores today. I do not know personally. But if you take the present cost minus depreciation, it may not be less than Rs. 6 lakh crores. Therefore, the first mistake committed by the Government is that disinvestment has been resorted to by taking into account a lower value of the assets. And who is going to pay for it? It is the nationalised banks and the people who are going to pay for it. It is the people's money invested in the public sector. You are the custodian of that money and you have to safeguard the interest of the people, the country and the exchequer. Therefore, when you are again disinvesting the shares of the public sector, the present market value of the assets should be taken into account and on that basis only you should fix the price of the shares. Otherwise, I am afraid, you will lose a lot of money. If you are not going to do it on this basis, you will lose a lot of money. Already, you have lost about Rs. 20,000 crores in the transactions. The Government has lost Rs. 20,000 crores. If that money had come to the Government, you could have given the money again to the public sector. Of crores, you have got that money. You have got it because it is your share capital. But I would urge upon the Government that not only for the purpose of balancing your deficit, but also for the purpose of reviving certain public sector undertakings, the money should be used. A major portion should be given to those public sector undertakings which you want to revive. Where you feel that these are the public sector undertakings which should be revived, you should pump in more finances from out of the money which you get by disinvesting the shares of the PSUs. The Government will get huge profits. In the case of the private sector, even in the case of a company in the lower rung, the value of the share is three or four times more than the book value. If this is the case, you can imagine what will be the value of the shares of the PSUs. This should also be taken into account. I would, therefore, urge upon the Government that when they again go in for disinvestment of the shares of the public sector, they should see that they are properly valued.

Then, we hear it being said every time that the return is just 2 or 3 per cent. The Minister also says the same thing every time. I do not know what Mr. Thungon is going to say. You say that the total invesment in the public sector is Rs. 1,14,000 crores and that out of this, the return is just 2 per cent, i.e. Rs. 3,000 crores. But I would like to point out that a major part of it is by way of loans. Only Rs. 44,000 crores is by way of capital and Rs. 70,000 crores is by way of loans, on which you are getting interest from the public sector. If you want to calculate the actual rate of return, this interest should also be added to the profits.

Of course, in the public sector there are good companies as well as bad companies. There are some good companies. There are some bad companies. Only yesterday, I read the Finance Minister saying that he would like to have trusteeship kind of approach in industry. I agree with him. But I would draw

his attention to the fact that it is the public sector which is doing it, not the private sector. How much are you spending on the welfare of the workers, on health, on education, on maintaining the townships which you have constructed? They are spending Rs. 1,200 crores; Rs. 600 crores on maintenance and another Rs. 600 crores on education, health, etc. Should that be taken into account when you arrive at the profits? This is an amount which has been spent on the welfare of the employees. Therefore, this should not be taken into account. If you say that there should be trusteeship approach, you should also follow it. The amount spent on the welfare of the employees should not be taken into account.

Another point is, the loss incurred by the public sector industries which were taken over earlier from the private sector. I do not have the figures for the year 1991-92. We have not got it. But the figure for the earlier year is about Rs. 480 crores. This should have been taken into account when you are talking about profits and rate of return. Of course, I do feel that the public sector industries can do much better. But one should not condemn the public sector outright. (*Time-bell*) Madam, I will just make two or three points more.

I have with me here a document in regard to the Eighth Plan. I will just read out one paragraph from this document. This is in regard to the public sector. It says:

> "The public sector has numerous achievements to its credit. The development of our crucial infrastructure sector has been pioneered by the PSUs. Other vital segments of the industrial sector have been built up by public enterprises. The public sector has contributed richly to the widening and diversification of our industrial structure. The public sector will continue to perform a key role in the coming years."

Now, how are you going to achieve that? This is what you have said in the Plan document, but from your action it seems nothing formidable is going to be achieved. I am happy that the hon. Prime Minister has come. He has also the charge of the Ministry of Industry. Sir, before you came I was trying to say that while revaluing the shares we should take into account the cost of the land which has gone up. In some cases, it has gone up by ten, twenty, thirty times. For example, in Bombay the cost of one square metre of land is Rs. 10,000. So, while fixing the value of shares all these costs should be taken into account. You must allow depreciation for plant and machinery and if all these things are taken into account, I feel, you would be able to get many times more than Rs. 2500 crores which you have got now. While fixing the value of shares you can give some margin, some concession. In this way, the Government could get huge finance. From that some part you could use for the purpose of reducing the deficit and some part you could use for the purpose of those industries which are sick but which could be made viable. If this is done, the sick industries, where there is a problem of employment, could be revived and then there would be no problem of employment.

[**The Deputy Chairman** in the Chair]

As I said earlier, budgetary allocation is going down year by year. We are getting about Rs. 20,000 crores every year from the public sector by way of excise, customs and corporate tax. I think, that amount should also be stepped up because public sector is the only sector which cannot hide excise duty, which cannot conceal corporate tax, and as such, it should be treated differently. Now the Unit Trust of India got Rs. 4500 crores in only one scheme. Public sector should be given enough finances so that this problem could be sorted out. I think 85 per cent of the capital investment in the public sector is a fairly reasonable rate of return as has been mentioned by you in your monograph. If you all help the public sector, our goal

[Shri Jagesh Desai]

would be achieved. For infrastructure industry also you have to determine a fair amount of return so that we can, by efficiency, achieve that goal.

Lastly, Madam, here is the "Employees" Plan to turn around" which has been prepared by the National Projects Construction Corporation Limited. I have gone through this. They have given all the details. They say that if the workers are given a say in policy-making, in management, they can turn round the industry. I will give this to you. I feel that it is a very good scheme. They have given suggestions as to how sick industries could come up. The Government should examine this kind of a plan and wherever feasible, the Government adopt some of these suggestions so that these industries can again be revived.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We have still five minutes. Mathur Sahib.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : महोदया, मैंने दोनों मित्रों का भाषण बहुत ध्यान से सुना। ऐसा लगा कि दोनों लोग इस बात के हामी हैं कि पब्लिक सैक्टर जैसा है वैसा न रहकर और बढ़ाया जाए मेरी पार्टी ने जब गत वर्ष नई उद्योग नीति की घोषणा की गई थी तो उद्योग नीति का मोटे तौर से स्वागत किया था क्योंकि जितना महत्व हिन्दुस्तान की आज़ादी के बाद पब्लिक सैक्टर को दिया गया वह आज हमें यहां लाकर खड़ा कर देगा, इस बात की आशंका हमें पहले से थी लेकिन जैसा कहते हैं, देर आयद दुरुस्त आयद। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पब्लिक सैक्टर के विरोध में है, लेकिन उसकी सीमाएं होनी चाहिए। यदि हमारा कथन जो आज से 30 साल पहले हमने कहा था मिथ्या होता तो आज की स्थिति में आकर कांग्रेस की सरकार को अपनी नीति को पलटना न पड़ता। यह भी स्थिति आई कि हमें मजबूर हो कर विदेशी ऋण लेना पड़ा है। यह तो मैं नहीं कहता, सच क्या है मैं नहीं जानता लेकिन जो कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं वह आई०एम०एफ० के दवाब के अंदर किए गए हैं। सच्चाई सरकार कभी स्वीकार नहीं करेगी लेकिन चाहे पब्लिक सेक्टर को घटाने का सवाल हो, चाहे मजदूरों का सवाल हो, चाहे उसके साथ जुड़ी हुई उद्योग नीति का सवाल हो, आज हमारे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा सिवाय इसके कि हम आई०एम०एफ० की शरण में जाएं यदि हमने नीति बदली होती स्वयं की इच्छा से तो हिन्दुस्तान के लोग आपकी तारीफ करते, लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार को नीति बदलनी पड़ रही है क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है।

जहां तक पब्लिक सैक्टर का सवाल है, उसके संदर्भ में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने नेशनल रिवाल्विंग फंड के माध्यम से वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं लिया है? आपने लोन लिया है। लेकिन मज़ाक की बात यह है कि जब प्रथम बार मजदूरों के साथ बैठक हुई तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर महोदय ने कहा कि दो करोड़ रुपए काफी होंगे। लोग हंसने लगे कि दो करोड़ रुपए से क्या होगा। तो बाद में कहने लगे कि दो सौ करोड़ होगा। मेरे पास फिगर्स हैं 148.75 करोड़ रुपया बजट में रखा गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या नेशनल रिवाल्विंग फंड में दो सौ करोड़ रुपया कारखानों को दोबारा चलाने के लिए या मजदूरों के रिहेबिलिटेशन के लिए पर्याप्त होगा? कोई भी कहेगा कि यह असंभव है। जहां करोड़ों रुपया लगता है, वहां कारखाने बंद हो जाएं, उन सब की पूर्ति के लिए इतना पैसा काफी होगा? मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मंत्री महोदय आपने कहा था कि वर्ल्ड बैंक से हम दो बिलियन डॉलर हर साल लेंगे। टू बिलियन डॉलर ऐवरि एयर और वर्ल्ड बैंक का क्या कहना है? वर्ल्ड बैंक का कहना है कि यदि सारे कारखाने ठीक करने हैं तो 30 बिलियन डालर की आवश्यकता होगी। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि आप जहां पर खड़े हैं क्या आपने कोई नीति बनाई है, आपने कोई ऐस्टिमेंट लगाया है कि आपको दो सौ करोड़ रुपये की राशि पर्याप्त

होगी अथवा नहीं ? यदि नहीं होगी तो आप क्या करने जा रहे हैं ?

महोदया, साढ़े तीन बज गए, मैं अब बैठता हूं। बाकी बात बाद में कहूंगा।

STATEMENT BY PRIME MINISTER ON RAM JANAMBHOOMI-BABRI MASJID DISPUTE—Contd.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now we can continue with the clarifications, suggestions rather. Shri P. Upendra... (*Interruptions*)...

SHRI SUKOMAL SEN: Madam, please let me finish.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay, we are in the 29th minute. You can have one minute.

SHRI SUKOMAL SEN: Madam, I will put only two questions to the hon. Prime Minister.

The fact is that despite the court orders, one by the Lucknow Bench of the Allahabad High Court and the other by the Supreme Court, the construction has been made, a big construction has been made. Now it has stopped, it is reported.

Now, what will happen? Will the country now see that despite the Courts' instructions, the Courts' rullings, defying the Court rullings, construction can be made, for ten days it can be constructed and it can remain, it can exist? Will country see so? What is the Prime Minister going to do about the construction?

Secondly, the last question is that both the BJP and the VHP have openly, publicly declared that it is a question of faith, not a question of a judgement by the court and that if the court verdict would go against them, they would not abide by it. They are raising the issue in such a way that the court is also ultimately pressurised. That is the intention. In the situation, it is my feeling that by talking to them and by not taking into confidence any political party in the country, the countrymen of India, the Prime Minister is actually on a tiger. Does the Prime Minister understand this position? And I would like to know, when he is riding on a tiger, how he wants to get out of it.

Thank you.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): There is the NIC to take an appropriate decision. Don't forget that... (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think that this House represents all political parties, does it not?

SHRI P. UPENDRA (Andhra Pradesh): Madam, the whole country heaved a sigh of relief at the cessation of the *kar seva*. We have indeed passed through a period of great tension during the last three weeks or so.

I must congratulate the Prime Minister for his patient and tactful handling of the sensitive and delicate situation. It shows that patience generally pays, if not always.

I should also compliment him for his very balanced and factual statement which is free from polemics, which does not blame anybody.

I particularly liked the portion where he mentioned that he would continue the efforts of the previous Governments in settling this issue. That shows that the policy of the Government, of whichever complexion it is would be that it would continue the efforts of maintaining, upholding secularism, communal harmony in this country.

There is one section which also requires to be complimented. That is our Muslim brothers and sisters who extraordinarily kept themselves cool at the greatest of provocation when the High Court orders were being blatantly violated. Otherwise, there would have been a great communal conflagration in the country by now.